कानपुर, मंगलवार, 27 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 28, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम...>Pg12

अवैध प्लाटिंग पर गरजा केडीए का बुलडोजर...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

यूजीसी के नए नियमों पर देशव्यापी उबाल

नए यूजीसी नियमों के विरोध ने पकड़ा तूल, इस्तीफों से बढ़ी सियासी-प्रशासनिक हलचल, सरकार ने शुरू की जांच

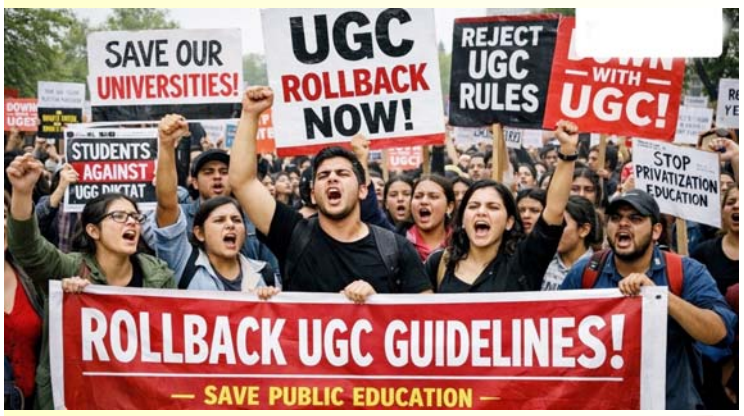

- यूजीसी के नए नियम लागू होने के बाद देशभर में विरोध और प्रदर्शन तेज
- बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने नियमों के विरोध में दिया इस्तीफा
- इस्तीफे के बाद शासन ने सिटी मजिस्ट्रेट को किया सस्पेंड, विभागीय जांच के आदेश
- दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर छात्र व सामाजिक संगठनों का जोरदार प्रदर्शन
- नियमों को लेकर संविधान, सामाजिक संतुलन और निष्पक्षता पर उठे सवाल
- विपक्ष ने सरकार पर बिना विमर्श के नियम लागू करने का आरोप लगाया
- सत्तापक्ष का दावा–नियमों का उद्देश्य समानता और पारदर्शिता बढ़ाना
- मामला अब राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी विवाद का रूप लेता जा रहा है

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली/बरेली। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध तेज हो गया है। इस विवाद ने उस समय गंभीर मोड़ ले लिया जब उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट और मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी ने नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजधानी दिल्ली में यूजीसी कार्यालय के बाहर छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए।

यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए नियमों को लेकर आरोप है कि इन्हें बिना व्यापक चर्चा के लागू किया गया, जिससे शिक्षा व्यवस्था में असंतोष फैल रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इन प्रावधानों से उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होंगे।

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा कि वे इन नियमों से सहमत नहीं हैं और इसे संविधान की भावना के विपरीत मानते हैं। इस्तीफा सामने आते ही शासन ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया और निलंबन के साथ जांच बैठा दी। इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में भी बेचैनी देखी जा रही है।

इधर, मध्य प्रदेश में एक आपीएस अधिकारी के इस्तीफे की चर्चा ने संकेत दे दिया है कि असंतोष केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। वहीं दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की और नियमों को वापस लेने की मांग की। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा गरमा गया है। विपक्षी दलों ने इसे शिक्षा व्यवस्था में मनमानी करार दिया है, जबकि सत्तापक्ष का कहना है कि नए नियम समानता और पारदर्शिता के उद्देश्य से लाए गए हैं। मामला अब सड़क, सचिवालय और अदालत तक पहुंचता दिख रहा है।

➪ बरेली सिटी मजिस्ट्रेट व एमपी के आईपीएस का इस्तीफा, सिटी मजिस्ट्रेट सस्पेंड, दिल्ली में प्रदर्शन

विरोध के मुख्य कारण

विरोध करने वालों का कहना है कि नियम केवल कुछ वर्गों को केंद्र में रखते हैं, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान नहीं हैं। नियमों में फर्जी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत की स्थिति में क्या कार्रवाई होगी, यह स्पष्ट नहीं है। इससे संस्थानों में डर और असंतुलन पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। संविधान के समानता के सिद्धांत पर सवाल पर आलोचकों का तर्क है कि यह नियम समानता की जगह वर्ग आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जो अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के खिलाफ हो सकता है।

क्या हैं यूजीसी के नए नियम?

यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। इनका औपचारिक नाम इक्यूटी / एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन बताया जा रहा है। नए नियमों के प्रमुख प्रावधान में हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी (Equity Committee) का गठन अनिवार्य। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों की शिकायतों के लिए विशेष शिकायत निवारण तंत्र। जातिगत भेदभाव की शिकायत पर त्वरित जांच और कार्रवाई का प्रावधान। संस्थानों को हर साल यूजीसी को अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य। नियमों का उल्लंघन होने पर संस्थान की मान्यता या फंडिंग पर असर पड़ सकता है। यूजीसी का कहना है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 46 की भावना के अनुरूप हैं और कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के लिए जरूरी हैं।

सरकार और यूजीसी का पक्ष

यूजीसी और सरकार का कहना है कि नियमों का उद्देश्य किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करना और सुरक्षित माहौल बनाना है। सरकार का दावा है कि आवश्यक हुआ तो नियमों में सुधार पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि यह नियम किसी के खिलाफ नहीं है। विपक्ष इसे मुद्दा बना कर भ्रम फैला रहा है। उधर माना जा रहा है कि यूजीसी के नए नियम अब सिर्फ शैक्षिक सुधार नहीं रह गए हैं। यह मुद्दा बन चुका है सामाजिक संतुलन, संवैधानिक समानता, प्रशासनिक स्वतंत्रता और राजनीतिक बहस का केंद्र। आने वाले दिनों में यह विवाद सुप्रीम कोर्ट, संसद और सियासत तीनों स्तरों पर और गहराने के संकेत दे रहा है। अधिकारियों और शिक्षकों का कहना है कि इससे संस्थानों की स्वायत्तता कम होगी और प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ेगा।

77वें गणतंत्र दिवस पर सेवा भारती को मिली एंबुलेंस सेवा की सौगात

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेवा भारती कानपुर प्रांत द्वारा एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। यह सेवा एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड कानपुर के सीएसआर सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई।

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उमेश सिंह द्वारा सेवा भारती कानपुर प्रांत के उपाध्यक्ष अरविंद सक्सेना को एंबुलेंस की चाभी सौंपकर हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ कराया गया। प्रांत महामंत्री रामशंकर ने इस सहयोग के लिए फैक्ट्री प्रबंधन का आभार व्यक्त किया।

विभाग मंत्री जय भदौरिया ने बताया कि इस एंबुलेंस सेवा के माध्यम से सेवा भारती कानपुर प्रांत अपने स्वास्थ्य आयाम से जुड़े सेवा कार्यों को और अधिक सशक्त बनाएगा।

उन्होंने कहा कि एंबुलेंस के जरिए दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले वंचित वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, जिससे स्वस्थ भारत की संकल्पना को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड प्रबंधन के कंपनी सचिव मनीष सिंह,

निदेशक वित्त जय गोपाल महाजन, निदेशक मानव संसाधन मानस कविराज,

कार्यकारी निदेशक किशोर गुरुदशानी तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन अनुप मुखर्जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

शास्त्री नगर में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य ध्वजारोहण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर।शास्त्री नगर स्थित स्मृति शेष राममूर्ति मिश्र वाटिका, छोटा सेन्टर पार्क में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का उल्लास देखने को मिला। इस अवसर पर 47 फुट लम्बे पोल पर भव्य ध्वजारोहण किया गया।

ध्वजारोहण भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित द्वारा किया गया।

कार्यक्रम का संयोजन पूर्व पार्षद राघवेन्द्र मिश्र ने किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ उपस्थित जनसमूह ने तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय नागरिकों, कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों की सहभागिता रही।

वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान की मर्यादा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के समापन पर देशभक्ति के नारों के साथ वातावरण राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हो गया।

उदयपुर गांव में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन

कमजोर लोगों की सहायता हेतु कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन बिधनू ब्लॉक के उदयपुर गांव में किया गया।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। आयोजन से समाज के वंचित वर्ग को राहत और संबल मिला। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।भारतीय नमो संघ के प्रदेश सचिव रामसेवक राहुल अवस्थी ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के सेवा कार्य लगातार जारी रहेगा।

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अंत्योदय और जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर भारतीय नमो संघ द्वारा समाज सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में ठंड के मौसम को देखते हुए क्षेत्र के निस्सहाय एवं आर्थिक रूप से

गणतंत्र दिवस पर मजदूर को बनाया मुख्य अतिथि

समानता और संविधान की भावना का दिया संदेश

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर।गणतंत्र दिवस के अवसर पर वासू इंटर प्राइज़ेज़ और लोकहितार्थ शीतऋतु में गरीबों की सहयोगी विंटर मिशन टीम द्वारा आयोजित समारोह में सामाजिक समानता और संविधान की मूल भावना को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। आमतौर पर ऐसे आयोजनों में जनप्रतिनिधि या अधिकारी मुख्य अतिथि होते हैं, लेकिन इस बार दिहाड़ी मजदूर बबलू कुमार को मुख्य अतिथि बनाकर एक प्रेरक संदेश दिया गया।मुख्य अतिथि बबलू कुमार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी,

जिसके बाद उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया। समारोह में कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के सहायक आयुक्त आरएस देवल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने बबलू कुमार को माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने संविधान की महत्ता, समान अधिकार और गणतंत्र के मूल मूल्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गरीब परिवारों के बच्चों को नोटबुक और स्टेशनरी वितरित कर शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया।समारोह में शिवराम सिंह, सुरेश कुमार वर्मा, शैलेन्द्र सचान, अजय सिंह, भूपेंद्र यादव, वर्षा केसरी, अजय केसरी, श्रेष्ठ और राशि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन संयोजक रोहित लाल और विंटर मिशन टीम के पंकज कुमार सिंह ने किया।

इनको मिला समाज गौरव सम्मान

समारोह के दौरान समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नर अवार्ड से सम्मानित शिक्षक राजन लाल कमल, निर्धनों को निशुल्क शिक्षा देने वाले शिक्षक आरसी पाल, अंधविश्वास निर्मूलन के लिए जादूगर पीसी कानपुरी, लोकहित के कार्यों के लिए प्रोफेसर डॉ सुभाष चंद्रा तथा निशुल्क शिक्षा, गरीबों के अधिकार और युवाओं के करियर विकास के लिए कार्य करने वाले रामावतार गौतम को सम्मान प्रदान किया गया।इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि गणतंत्र में सबसे बड़ा पद नागरिक का होता है और सम्मान का अधिकार हर वर्ग को समान रूप से प्राप्त है।

अवैध प्लाटिंग पर गरजा केडीए का बुलडोजर

केडीए के ओएसडी डॉ रवि प्रताप सिंह ने की बिठूर क्षेत्र में ध्वस्तीकरण, सीलिंग की कार्रवाई

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और अनाधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई जारी है। उपाध्यक्ष मदन सिंह गब्रयाल के निर्देशन में मंगलवार को प्रवर्तन जोन-1बी द्वारा व्यापक ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई।

विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में मटका चौराहे से जंगल वाटर पार्क मोड़, भगवान बुद्ध आश्रम के पीछे लगभग 4.5 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। केडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही इस प्लाटिंग में बने रोड, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट सहित समस्त संरचनाएं 3 जेसीबी मशीनों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन टीम के साथ थाना बिठूर का पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा।

इसी क्रम में सिंहपुर कछार क्षेत्र में सिंहपुर चौराहे से सब्जी मंडी की ओर प्रेमपुर के आगे स्थित लगभग 5.5 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति किए गए निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(क) के अंतर्गत सील किया गया।

केडीए के ओएसडी ने कहा आम जनमानस से अपील की कि प्राधिकरण क्षेत्र में भूमि क्रय करने से पूर्व कानपुर विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें तथा भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक और मानसिक क्षति से बचा जा सके। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कल्याणपुर और बिठूर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में लगभग 11 बीघा क्षेत्रफल की अवैध प्लाटिंग और निर्माण को चिन्हित किया जा चुका है, जिन पर शीघ्र ही सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है।

– डॉ रवि प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी, कानपुर विकास प्राधिकरण

दो वर्ष पूर्व 26 जनवरी के दिन महापौर प्रमिला पाण्डेय ने 150 फ़ीट ऊंचाई पर तिरंगा

घंटाघर पर नहीं लहराया तिरंगा, गणतंत्र दिवस पर सूना रहा चौराहा

स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर जहां पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, वहीं कानपुर के दिल कहे जाने वाले घंटाघर चौराहे पर इस बार एक बड़ी कमी साफ महसूस की गई। 26 जनवरी के अवसर पर 150 फ़ीट ऊंचाई पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जिससे शहरवासियों में मायूसी और निराशा का माहौल देखने को मिला।

गौरतलब है कि दो वर्ष पूर्व 26 जनवरी के दिन मेयर प्रमिला पाण्डेय द्वारा 150 फ़ीट ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया था, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हुई थी। उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लोग दूर-दराज़ के इलाकों से घंटाघर चौराहे पर पहुंचे थे। देशभक्ति गीतों से गूंजता चौराहा और लहराता विशाल तिरंगा कानपुर की शान बन गया था।

स्थानीय दुकानदार गुड्डू गुप्ता ने कहा 150 फ़ीट ऊंचाई पर तिरंगे को देखकर दिल में अपने आप ही हर्ष और उल्लास भर जाता था। इस बार सब कुछ सूना-सूना सा लग रहा है। वहीं उन्नाव से आए यात्री परवेज़ ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा,÷मैं हर साल 26 जनवरी को अपने बच्चों को घंटाघर चौराहे पर 150 फ़ीट ऊंचा झंडा दिखाने लाता हूं। इस बार खास तौर पर उन्नाव से आया था, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को निराशा ही हाथ लगी। वहीं स्थानीय दुकानदार संतोष ने कहा, ये तो बहुत दुख की बात हैं हर वर्ष 26 जनवरी या 15 अगस्त को चौराहे पर देश भक्ति गीतों के साथ 150 फिट ऊंचाई पर फैहरने वाला तिरंगा इस बार नहीं लगा। शहरवासियों का कहना है कि हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को घंटाघर चौराहे पर देशभक्ति गीतों के बीच 150 फ़ीट ऊंचाई पर तिरंगा फहराया जाना एक परंपरा बन चुकी थी, लेकिन इस बार तिरंगे की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

नगर निगम मोतीझील में संयुक्त मोर्चा का हल्ला बोल

» कर्मचारियों की भारी भीड़ से गूंजा निगम परिसर

» कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम संयुक्त मोर्चा द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत बुधवार को नगर निगम परिसर में कर्मचारियों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में कर्मचारी नगर निगम पहुंचने लगे, जिससे परिसर कर्मचारियों की भीड़ से भर गया और माहौल पूरी तरह आंदोलित नजर आया।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि उनके अधिकारों की लड़ाई किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ेगी। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा।

संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों में रमाकांत मिश्रा,मुन्ना हजारिया, हरिओम बाल्मिकी, अजीत बाघमार और चालक संघ अध्यक्ष विनोद कुमार आदि ने कहा कि नगर निगम में कार्यों के निजीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी नेता उस्मान अली का कहना है कि बार-बार आश्वासन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से मांग की कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े फैसले तुरंत लिए जाएं। संयुक्त मोर्चा के कमरूद्दीन ने कहा कि यदि बातचीत के नाम पर समय टालने की नीति अपनाई गई तो कार्यबंदी और हड़ताल के लिए पूरा मोर्चा तैयार है।

नगर निगम परिसर में कर्मचारियों की भारी मौजूदगी के चलते दिनभर गतिविधियां प्रभावित रहीं और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। इस दौरान तमाम कर्मचारी की ताकत के साथ मौजूद रहे ।

यूजीसी को लेकर भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

सामाजिक समरसता और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की उठाई मांग

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू यूजीसी के नवीन एक्ट को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में उत्पन्न हो रही भ्रांतियों, आशंकाओं और मानसिक असुरक्षा की भावना के समाधान के लिए भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीन कुमार शुक्ल ने प्रधानमंत्री को एक विस्तृत पत्र भेजा है।

पत्र के माध्यम से प्रवीन कुमार शुक्ल ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर, सामाजिक समरसता और योग्यता आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है,

लेकिन यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू किए गए जाति आधारित भेदभाव निरोधक प्रावधानों की भाषा और प्रक्रिया को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है।

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि भेदभाव का विरोध समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में एक्ट के कुछ प्रावधान ऐसे प्रतीत होते हैं, जिनसे व्यवहार आधारित निष्पक्षता के स्थान पर जातिगत पहचान को अधिक महत्व मिलने की आशंका उत्पन्न हो रही है।

प्रवीण कुमार शुक्ल

इससे शिक्षा परिसरों में आपसी विश्वास के बजाय अविश्वास और मानसिक दबाव का वातावरण बनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रवीन कुमार शुक्ल ने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक देशभर में विराट हिंदू सम्मेलन जैसे आयोजनों के माध्यम से जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार के प्रावधानों को लेकर संशय की स्थिति बनना सामाजिक एकता और समरसता के प्रयासों के विपरीत प्रतीत होता है।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस विषय पर शीघ्र आवश्यक स्पष्टीकरण और संतुलित सुधार किए जाएंगे, जिससे शिक्षा का वातावरण भयमुक्त, विश्वासपूर्ण और राष्ट्र निर्माण के अनुरूप बना रहेगा।

सम्पादकीय

नागरिकों की जवाबदेही-जागरूकता भी जरूरी

ऐसे वक्त में जब हम 77वां गणतंत्र दिवस समारोहपूर्वक मना रहे हैं, सत्ताधीशों के साथ-साथ देश के नागरिकों के लिए भी यह आत्ममंथन का समय है। निर्विवाद रूप से, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा हमारी संवैधानिक संस्थाओं की जनपक्षधरता और जवाबदेही से सुनिश्चित होती है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे जनतंत्र पर तंत्र हावी न हो। नागरिकों का जीवन सुगम हो और सत्ता व प्रशासन तक उनकी पहुंच सहज हो। वहीं, नागरिकों को भी संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली और जवाबदेही पर सचेतक निगाह रखनी चाहिए। देश का स्वतंत्र मीडिया जनहितों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि समाज में असीम शक्ति होती है। समाज का सक्रिय समर्थन किसी योजना और नीति को बदलाव के आंदोलन में बदल देता है। देश में डिजिटल पेमेंट में जनभागीदारी का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया के आधे डिजिटल पेमेंट भारत में होते हैं। निःसंदेह, देश में लोकतंत्र की समृद्ध परंपराओं को जनभागीदारी से ही अक्षुण्ण रखा जा सकता है। देश ने कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। हमारे लोकतंत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने में हमारे वयस्क मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में हावी होते धनाढ्य लोग, बाहुबलियों और दागी उम्मीदवार तभी दरकिनार हो सकते हैं, जब मतदाता विवेकपूर्ण मतदान के जरिए समाज के जागरूक, ईमानदार और आम उम्मीदवारों को जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लिए चुनेंगे। हाल के वर्षों में देश के लोकतंत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। उनका मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। बल्कि, उन्होंने कई राज्यों में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि खेत-खलिहान से अंतरिक्ष तक और सेना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में विशिष्ट पहचान बनाने वाली महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को हमारी सरकारों को प्राथमिकता की सूची में शामिल करना होगा। बड़े पैमाने पर जनधन खाते खुलने, आवास योजनाओं में संपत्ति का अधिकार मिलने और स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी से देश की करोड़ों महिलाएं सशक्त बनी हैं। वहीं, हमारा सौभाग्य है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। आज जरूरत इस बात की है कि युवा आबादी को पर्याप्त और समय पर रोजगार मिले। कौशल विकास योजनाओं से उन्हें स्वावलंबी बनाने का मार्ग सुनिश्चित किया जाए।

यदि हम हर युवा को रोजगार देना सुनिश्चित कर सकें, तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर सकते हैं। हमें दुनिया के तमाम देशों में रोजगार की तलाश में भटक रहे युवाओं को देश में ही सम्मानजनक रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए।वहीं दूसरी ओर, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसानों को फसलों का न्यायसंगत दाम देने के प्रयास तेज़ करने होंगे। सस्ते ब्याज वाले ऋण, बीज और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करके हम उनकी राह आसान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों को राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है।लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारे जनतंत्र पर तंत्र हावी न हो। नागरिकों का जीवन सुगम हो और सत्ता व प्रशासन तक उनकी पहुंच सहज हो। वहीं, नागरिकों को भी संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली और जवाबदेही पर सचेतक निगाह रखनी चाहिए। देश का स्वतंत्र मीडिया जनहितों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश में डिजिटल पेमेंट में जनभागीदारी का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया के आधे डिजिटल पेमेंट भारत में होते हैं। निःसंदेह, देश में लोकतंत्र की समृद्ध परंपराओं को जनभागीदारी से ही अक्षुण्ण रखा जा सकता है। देश ने कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। हमारे लोकतंत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने में हमारे वयस्क मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र में हावी होते धनाढ्य लोग, बाहुबलियों और दागी उम्मीदवार तभी दरकिनार हो सकते हैं,बड़े पैमाने पर जनधन खाते खुलने, आवास योजनाओं में संपत्ति का अधिकार मिलने और स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी से देश की करोड़ों महिलाएं सशक्त बनी हैं।

क्रिकेट को रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने दें

यशवंत सचदेव

आज भारत और बांग्लादेश का युवा कहीं अधिक आकांक्षी और महत्वाकांक्षी हैं। इसीलिए क्रिकेट नई शुरुआत करने का एक माध्यम बन सकता है। दोनों पक्षों के बीच तनाव को खत्म कर सकता है।भारत-बांग्लादेश संबंधों के मौजूदा संकट में रोचक पहलू यह कि समाधान हेतु उपयुक्त तमाम घटक उसमें ही मौजूद हैं। भारत के लिए अवसर है कि नकारात्मक सोच वाले उन सभी विरोधियों की बाजी पलट दें जो 1971 के बाद से दो मुल्कों के बीच बेहद खास रिश्तों का पराभव चाहते हैं। समाधान हेतु मुद्दों की सूची में शीर्ष पर क्रिकेट संकट है, जो एक पखवाड़े पहले हिंदू संगठनों द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के खेलने पर रोक लगाने की मांग से पैदा हुई। बीसीसीआई इस मांग पर झुक गई और युवा मुस्तफिजुर को हटाया गया। इससे क्रोधित हुए बांग्लादेशियों का गुस्सा थम नहीं रहा है। उन्होंने टी-20 विश्व कप में भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है, जिसमें कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डंस स्टेडियम में होने वाला मैच भी एक है। उनकी मांग थी कि उनसे संबंधित क्रिकेट मैच, ठीक पाकिस्तान की तरह, तटस्थ देश श्रीलंका स्थानांतरित किया जाए। फिर, यहां एक विचार है।

संभवतः बांग्लादेश संबंधित मैचों को दक्षिण भारत में स्थानांतरित कर दिया जाता, जहां पर बंगाली दर्शक कम होते हैं। संभव है उन्हें अमिताव घोष द्वारा पिछले दशकों में, बहुत डूबकर लिखे तीन नॉवेल (द शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड, गन आइलैंड) के झकझोर देने वाले विषय-वस्तु का इतनी गहराई से अहसास न हो। अब शीर्ष भाजपा नेतृत्व के लिए समय आ गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से राब्ता बनाएं -और बीएनपी भी यही करेङ्क हालांकि बीएनपी प्रमुख, तारिक रहमान, इन दिनों 12 फरवरी को होने वाले चुनावों की तैयारी के लिए रैलियों-बैठकों के साथ देश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आखिरकार, यदि आरएसएस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बात कर सकती है, तो शेष कुछ भी संभव है। यह विचार दोनों पक्षों के लिए है कि अपना चेहरा बचाएं, ठंडे दिमाग वालों को वार्ता करने दें ताकि गर्म दल वाले अवसर हथिया न सकें। हमारे द्विपक्षीय इतिहास में इससे भी बदतर घटित हुआ है। वास्तव में, 1971 में बना उत्साह लंबे समय तक टिका नहीं; चार साल से भी कम अवधि में, 15 अगस्त, 1975 को, बांग्लादेशी फिर से बांग्लादेशियों का कत्ल कर रहे थे। वर्तमान में लौटते हुए। आज की कहानी अब मुस्तफिजुर रहमान और यहां तक कि उन शेख हसीना के बारे में और अधिक नहीं रही, जिन्होंने द प्रिंट को दिए अपने साक्षात्कार में आगामी बांग्लादेशी चुनावों में आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने को 'बदलाव का रूप धरा अधिनायकवाद' बताया है। यह तथ्य कि उन्होंने दिल्ली स्थित विदेशी संवाददाता क्लब को एक वॉयस मैसेज जारी किया है, उसमें भी मूल रूप से वही संदेश था। (ऐसा कहा जा रहा है कि उनका क्लब में खुद मौजूद न रहना या वीडियो संदेश जारी न करना, उनसे बनी सहमति का एक हिस्सा है)। निस्संदेह, भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध -अगस्त 2024 में हसीना के तख्ता पलट और हाल ही में बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं की प्रतिशोध की भावना से की गई हत्याओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं- क्षति नियंत्रण तुरंत शुरू न करना बहुत नुकसानदायक होगा। एक शुरुआत हो चुकी है, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ढाका गए थे। पिछले नवंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान भारत में अपने समकक्ष अजीत डोभाल से मिलने दिल्ली आए थे। दोनों तरफ दांव बहुत बड़ा लगा है। भारत को न केवल विभिन्न जनजातियों, धर्मों, कुलों और राजनीतिक दलों के मिश्रण वाले संवेदनशील उत्तर-पूर्व अंचल की सुरक्षा के लिए बल्कि पूर्वी दिशा के मुल्कों के साथ रिश्तों में हो रहे तेजी से बदलाव के बीच बांग्लादेश के साथ की जरूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। कई लोग हसीना के अहंकार-कुशासन का हवाला देते हुए कहते कि उन्हें इसलिए उखाड़ फेंका गया। यह भी उतना ही सच है कि भारत ने बहुत कुछ नजरअंदाज किया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि शेख हसीना और बीएनपी का आपस में हमेशा बैर रहा है। बीएनपी ने दो बार राष्ट्रीय चुनाव का बहिष्कार किया, जिससे घरेलू राजनीतिक कलह बढ़ गई।

लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, शेख हसीना भारत की पसंदीदा क्यों बनी रहीं, इसका कारण यह है कि वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष रहीं। वे हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने को महत्वपूर्ण समझती थीं, खुली वार्ता के अलावा सीमापारीय व्यापार के पक्ष में थीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के नेतृत्व वाले घातक लोगों को घुसने नहीं दिया।

संस्थान को यूजीसी की मान्यता सूची से हटाना

नए ढांचे

डा0 सुधीर कुमार

हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नए नियमों को लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। इन नियमों के लागू होते ही सवर्ण समुदाय की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी हैं और इसके खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक यह दावा किया जा रहा है कि यह रेगुलेशन एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने के लिए लाया गया है और इसका दुरुपयोग कर छात्रों और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा। कई मंचों से भय का वातावरण बनाया जा रहा है और तथ्यों से परे जाकर तरह तरह का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भावनात्मक शोर और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर इन नियमों की वास्तविकता को समझा जाए।

सवाल उठता है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जिससे कुछ लोग डरे हुए हैं और क्या सचमुच यह किसी समुदाय के खिलाफ हैं? या फिर यह उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से चली आ रही असमानता और भेदभाव की समस्या से निपटने की एक कोशिश मात्र है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और यूजीसी के इन नियमों की सच्चाई आपके सामने रखने की एक कोशिश इस रिपोर्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026) को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम देश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य परिसर में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निवारण के

लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाना और वंचित सामाजिक समूहों को संस्थागत सहारा देना है।सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नए नियमों के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा। यह केंद्र न केवल भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा, बल्कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगा। विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना भी इसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। जिन महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, वहां यह कार्य संबद्ध विश्वविद्यालय के समान अवसर केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।हम आपको बता दें कि इन नियमों के लागू होने की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2012 में बने भेदभाव विरोधी नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी को अद्यतन नियम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर की गई थी। हम आपको याद दिला दें कि इन दोनों ही छात्रों के मामलों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न और संस्थागत उदासीनता को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ी थी।नए ढांचे के तहत समान अवसर केंद्र के साथ एक समानता समिति का गठन भी अनिवार्य होगा। इस समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और उसे प्रत्येक छह महीने में अपनी रिपोर्ट संस्थान तथा यूजीसी को भेजनी होगी। इसके अतिरिक्त, परिसर में भेदभाव की रोकथाम के लिए छोटी सतर्कता इकाइयों के रूप में समानता दस्तों का गठन भी किया जाएगा।नियमों में यह भी प्रावधान है कि समान अवसर केंद्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समूहों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके। प्रत्येक संस्थान में एक वरिष्ठ शिक्षक को इस केंद्र का समन्वयक नियुक्त किया जाएगा, जिसे वंचित समूहों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध माना गया हो। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो यूजीसी के पास कड़ी कार्रवाई के अधिकार होंगे। इसमें यूजीसी की योजनाओं से वंचित करना, डिग्री और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को रोकना, यहां तक कि संस्थान को यूजीसी की मान्यता सूची से हटाना भी शामिल है। इस बीच, इन नियमों के लागू होने के साथ ही देश के कुछ हिस्सों में विरोध के स्वर भी सुनाई दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। हम आपको यह भी बता दें कि आंकड़े दर्शाते हैं कि बीते वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में लगातार वृद्धि हुई है।

संविधान और गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी डॉ. संजीव दीक्षित ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में संविधान और गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इस अवसर पर तहसीलदार अनुभव चंद्रा, नायब तहसीलदार सीपी राजपूत, दिव्या भारती, रंजीत यादव, बार, द लायर्स, एवं एकीकृत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं तहसील के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद बिल्हौर परिसर में पालिकाध्यक्ष इकलाख खान ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी अंजनी मिश्रा, सभासद एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कस्बे के चिल्ड्रेन मेमोरियल पब्लिक स्कूल, बिल्हौर इंटर कॉलेज, अरौल स्थित एमएलकेडी पब्लिक स्कूल, जीपीआरडी कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों, पंचायत भवनों, मकनपुर मेला क्षेत्र एवं तहसील क्षेत्र के सभी थानों में ध्वजारोहण किया गया।

मदरसों में भी तिरंगा फहराया गया तथा तिरंगा यात्राएं निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया गया।

- बिल्हौर में देशभक्ति की भावना से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस
- तहसील, नगर पालिका, थानों व शिक्षण संस्थानों में हुआ ध्वजारोहण

बॉर्डर फिल्म के सीन पर बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति

अरौल स्थित एमएलकेडी पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीतों के साथ फिल्म बॉर्डर-2 के चर्चित सीन पर शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखकर दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। प्रधानाचार्य एन.बी. सिंह ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की।

एसआईआर कार्य में लगे बीएलओ हुए सम्मानित

गणतंत्र दिवस के अवसर पर तहसील परिसर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसडीएम डॉ. संजीव दीक्षित ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाए रखने में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निष्ठा और जिम्मेदारी से कार्य करने वाले बीएलओ की सराहना की।

पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे

पत्रकारिता और वर्तमान परिवेश पर गोष्ठी में की गई चर्चा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। कस्बे के बिल्हौर इंटर कॉलेज में पत्रकारिता और वर्तमान परिवेश को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बिल्हौर तहसील क्षेत्र के पत्रकारों ने हिस्सा लिया और पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे।

गोष्ठी में वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई।कार्यक्रम के दौरान नव मनोनीत अध्यक्ष अनुराग अवस्थी और महामंत्री नरेश पांडेय ने पत्रकारों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संगठन को और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने के लिए आपसी समन्वय और एकजुटता पर जोर दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा।

गोष्ठी में उपस्थित पत्रकारों ने बारी-बारी से अपनी बात रखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने में आने वाली समस्याओं को साझा किया। निष्पक्ष, जिम्मेदार और जनहितकारी पत्रकारिता पर जोर देते हुए सभी ने संगठन को सशक्त बनाने की आवश्यकता बताई।

मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर आशा बहुओं ने सौंपा ज्ञापन

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कोल्ड चेन हैंडलर द्वारा आशा बहुओं के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर सोमवार को आशा बहुएं बिल्हौर पहुंचीं। जिलाध्यक्ष आशा कुशवाह के नेतृत्व में आशा बहुओं ने एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई को वापस लेने की मांग की।

कोल्ड चेन हैंडलर विकास की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार 14 जनवरी को शिशुओं के नियमित टीकाकरण के लिए वैक्सीन कैरियर (एवीडी) के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन भेजी जा रही थी। इसी दौरान हड़ताल पर चल रही आशा बहुओं द्वारा वैक्सीन कैरियर अपने कब्जे में ले लिए जाने का आरोप लगाया गया है। तहरीर में कहा गया है कि वैक्सीन कैरियर रोके जाने के कारण टीकाकरण कार्य प्रभावित हुआ और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई। पुलिस ने मामले में अज्ञात आशा बहुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल तेज हो गई है। कोल्ड चेन हैंडलर द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को भी शिकायत भेजे जाने की बात कही गई है। वहीं, आशा बहुओं ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था। उन्होंने आरोप लगाया कि हड़ताल को दबाने के उद्देश्य से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आशा बहुओं ने ज्ञापन के माध्यम से मुकदमा वापस लेने की मांग दोहराई है।

- बिल्हौर एसीपी से मिलकर रखी अपनी बात

बीडीओ ने दरगाह जिंदा शाह मदार पर टेका माथा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर खंड विकास अधिकारी नेम चंद्र ने मकनपुर मेले का दौरा किया। इस दौरान ग्राम प्रधान मजाहिर हुसैन जाफरी के साथ उन्होंने दरगाह जिंदा शाह मदार पर पहुंचकर ज़ियारत की। दरगाह कमेटी के सदस्यों ने बीडीओ का परंपरागत रूप से पगड़ी बांधकर स्वागत किया, जिसके बाद बीडीओ ने दरगाह पर माथा टेककर दुआ मांगी।

दरगाह पर ज़ियारत के उपरांत बीडीओ ने ग्राम प्रधान के साथ मेले का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर साहिर हुसैन जाफरी ने बीडीओ को 'मकनपुरः इतिहास के आईने में' पुस्तक भेंट की। पत्रकारों से बातचीत में बीडीओ नेम चंद्र ने कहा कि मकनपुर मेला सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां दूर-दराज़ से लोग आते हैं और मेले के माध्यम से सैकड़ों दुकानदारों को रोज़गार मिलता है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान मेले की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।इस दौरान पंडित रामानुज,सागर, अनस समेत कई लोग मौजद रहे।

संकेतक के साथ जिम्मेदारी भी गायब चांदपुर-मलासा मार्ग पर जान जोखिम में

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

ग्रामीणों ने कहा, हादसे गिनता रहेगा प्रशासन या लगाएगा संकेतक

कानपुर देहात। एनएच-25 के चांदपुरङ्कमलासा मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही अब सवाल नहीं, अपराध बन चुकी है। तीखे और खतरनाक मोड़ों पर संकेतक, चेतावनी बोर्ड और रिफ्लेक्टिव साइन न लगाकर विभाग ने मानो दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण दे दिया है। इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।

रमपुरा गांव और अनंतपुरवा गांव के पास मौजूद तीखे मोड़ अंधेरे में मौत के फंदे बन चुके हैं।

तेज रफ्तार वाहन बिना किसी चेतावनी के सीधे मोड़ पर पहुंच जाते हैं और टक्कर हो जाती है। सवाल यह है कि जब हादसे हो चुके हैं, तब भी अब तक सुरक्षा संकेत क्यों नहीं लगाए गए? नई सड़क बनने के बाद वाहनों की गति कई गुना बढ़ गई है, लेकिन सुरक्षा इंतजाम शून्य हैं। रात के समय हालात और भी भयावह हो जाते हैं। अचानक सामने से वाहन आ जाने पर जान बचाना मुश्किल हो जाता है।

इस सड़क से रोज़ाना विद्यार्थी, बुजुर्ग, किसान और मजदूर गुजरते हैं, जिनकी जान हर पल खतरे में है। इस मार्ग पर कृषि उपज से लदे ट्रैक्टर और भारी मालवाहक वाहनों का दबाव भी लगातार बना रहता है। इसके बावजूद न स्पीड ब्रेकर लगाए गए, न दिशा सूचक, न ही चेतावनी बोर्ड।

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनाकर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह, मनोज पासवान, पिंटू यादव ,राजेश , गांव मलासा अशोक सिंह का कहना है कि हर दिन डर के साए में सफर करना मजबूरी बन गया है।

गांव में शहीद मूरत सिंह परिषदी माध्यमिक विद्यालय के समाने रोड पर ब्रेकर भारी आवश्यकता है फिर भी कोई ब्रेकर नहीं दिया गया। लोगों में दो टूक चेतावनी दी है कि यदि संवेदनशील मोड़ों पर तत्काल दिशा सूचक, रिफ्लेक्टिव चेतावनी बोर्ड, स्पीड ब्रेकर और संकेत चिह्न नहीं लगाए गए, तो भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े हादसे की पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन की होगी। इस प्रकरण में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता हेमंत कुनार से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका है।

नन्हे कलाकार ने चित्र में उकेरी देशभक्ति

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। दिल अगर देशभक्ति के भाव से भरा हो तो चित्र बनाते से समय भी वही अक्श दिखाई देगा।

इसी देशभक्ति की भावना को नन्हें कलाकार बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के छात्र आरव पुरवार की कूंची भी चित्र पर चली।

नन्हे कलाकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए लालकिले पर फहराता तिरंगा अपने चित्र में उकेरा। उसके चित्र को देखकर गुरुजनों व अन्य लोगों ने उसकी प्रशंसा की।

भटौली मोड़ से गढ़ेवा तक सड़क निर्माण कार्य शुरू

ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भटौली मोड़ से गढ़ेवा तक जाने वाले मार्ग के शेष हिस्से का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इससे पहले लगभग 6 महीने पूर्व विकास खंड अकबरपुर के ग्राम जगदीशपुर तक सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन जगदीशपुर से गढ़ेवा तक का हिस्सा अधूरा रह गया था, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

इस मार्ग को लेकर समाजसेवी शिवा पांडेय लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने बताया कि यह मार्ग उनके गांव के लिए सबसे अधिक भयावह स्थिति पैदा कर रहा था, खासकर बरसात के समय। इस समस्या को लेकर उन्होंने लंबे समय तक संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा था। लगभग 6 महीने पूर्व लखनऊ में इस समस्या से अवगत कराए जाने के बाद तत्काल संज्ञान लिया गया और लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसके बाद प्रमुख सचिव स्तर पर विषय पर चर्चा हुई और स्थानीय लोगों के सहयोग से अंततः सड़क निर्माण कार्य शुरू हो सका। सड़क का कार्य शुरू होते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है।इस अवसर पर रोहित दीक्षित, किशन बाजपेई, गोलू तिवारी, सलमान सिद्दीकी, नसीम खान, पप्पू प्रजापति, दिनेश गौतम, छोटे त्रिवेदी, आशीष पांडे, शिवम पांडे, जमील खान, बड़े तिवारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े कार्यों में भी सुविधा मिलेगी।

संविधान के मूल सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता समानता को अपनाने का किया आह्वान

कानपुर देहात में मनाया गया 77वाँ गणतंत्र दिवस, सीडीओ ने किया ध्वजारोहण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात में 77वाँ गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गरिमा एवं अनुशासन के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम विकास भवन परिसर में आयोजित हुआ। जहां मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ।

मुख्य विकास अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि 26 जनवरी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ।

उन्होंने संविधान के मूल सिद्धांत न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को अपनाने पर बल दिया तथा अधिकारियों व कर्मचारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस आत्मचिंतन का अवसर है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। कार्यक्रम के दौरान परिसर को तिरंगे रंगों से सजाया गया और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की एकता–अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरा आयोजन अनुशासन, गरिमा एवं राष्ट्रभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ।

पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर राष्ट्रभक्ति का उत्सव

तिरंगे फहरा कर समाज में भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात माती। देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर कस्बा गजनेर व सरवनखेडा में देशभक्ति और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। गजनेर व्यापार मंडल के तत्वावधान में पृथ्वीराज चौहान स्मारक, मुख्य चौराहा गजनेर व सरवनखेडा चौराहे पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष नीरज गुप्ता व सरवनखेडा उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उपस्थित व्यापारियों, ग्रामीणों और नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति नारों के बीच पूरे क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान वक्ताओं ने देश की आजादी, संविधान की महत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया। व्यापार मंडल के महामंत्री दीपू परिहार, कोषाध्यक्ष राजेश सचान, संरक्षक राकेश सिंह चौहान पूर्व प्रधान योगेंद्र सिंह चौहान उर्फ (बऊवा)सहित धर्मवीर परिहार, बऊवन साहू, शिवराज, कुलदीप, विमलेश, वसीम, सफीक, मुन्ना, सौरभ, शांतनु, रूही गुप्ता, कनिका गुप्ता, बालमुकुंद शुक्ला, सुखदाम सिंह, शेखर सिंह, तथा ग्राम सभा के गणमान्य नागरिक, दुकानदार बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

गणतंत्र दिवस: झंडारोहण के बाद दिलाई गई कर्तव्यनिष्ठा की शपथ

» स्कूली बच्चों को बताया शिक्षा व अनुशासन का संदेश देता गणतंत्र दिवस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील के विकास खंड मलासा स्थित राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलासा में गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण किया गया।

प्रधानाध्यापिका शीतला देवी ने ध्वजारोहण किया। छात्राओं, शिक्षकों, अतिथियों एवं अभिभावकों द्वारा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया।

इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका ने छात्राओं को विद्यालय, समाज, ग्राम एवं परिवार का सम्मान बनाए रखने, अनुशासन का पालन करने तथा सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहने की शपथ भी दिलाई। समस्त शिक्षिकाएं व ग्राम मलासा के ग्राम प्रधान पति वीरेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

गणतंत्र दिवस पर दिखा राष्ट्रप्रेम और उल्लास का वातावरण

» पीएम श्री विद्यालय बाढ़ापुर में गणतंत्र दिवस मनाया गया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। पीएम श्री विद्यालय बाढ़ापुर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत वातावरण में मनाया गया। विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडों, रंगीन गुब्बारों एवं सजावटी सामग्री से सजाया गय । प्रधानाध्यापिका कंचन यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। इसके बाद ÷भारत माता की जय÷, ÷वंदे मातरम÷ के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, ओजस्वी कविताएं एवं प्रेरणादायक प्रस्तुतियां दीं। बच्चों की प्रस्तुतियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान, संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानाध्यापिका कंचन यादव ने कहा कि ÷गणतंत्र दिवस हमारे संविधान की शक्ति और लोकतंत्र की नींव का प्रतीक है। आज के बच्चे ही कल के राष्ट्रनिर्माता हैं । शिक्षक सुमन यादव, सुरेखा यादव, दिनेश पाठक, दिव्या सक्सेना, उमा देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

प्रोत्साहन

अच्छे कार्यों का मिला इनाम

पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय को स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह

राहुल अग्निहोत्री/ स्वराज इंडिया

वर्ष 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं श्रद्धा नरेंद्र पांडेय

कानपुर देहात। कानपुर देहात में तैनात पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय की सख्त, निष्पक्ष और जनहितकारी पुलिसिंग को बड़ा सम्मान मिला है। गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर गृह मंत्रालय और पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी सूची में उनके नाम की घोषणा की गई, जिससे पूरे जिले के पुलिस महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई।

वर्ष 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा की ओर से स्वर्ण प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें अपराध नियंत्रण, माफिया विरोधी अभियान और आम जनता में कानून के प्रति विश्वास कायम करने के लिए दिया जा रहा है।पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय के नेतृत्व में जिले में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाए गए। आक्रामक पुलिसिंग के जरिए कई कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, जिससे जिले में अमन-चैन का माहौल बना। जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर उतारते हुए उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

श्रद्धा नरेंद्र पांडेय की कार्यशैली की खास बात यह रही कि उन्होंने केवल कार्यालयों तक सीमित न रहकर स्वयं सड़कों पर उतरकर आम लोगों की समस्याएं सुनीं। महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। गांवों और कस्बों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाकर जनता और पुलिस के बीच विश्वास का मजबूत रिश्ता बनाया।गरीबों, असहायों और पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनकी तत्परता ने खाकी की साख को नई मजबूती दी। संविधान और कानून को सर्वोपरि मानते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से किए गए उनके कार्यों को अब राज्य स्तर पर सराहा गया है।

उनके सम्मान की घोषणा होते ही जिले के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। सभी ने इसे पूरे पुलिस बल के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ऐसे सम्मान से ईमानदार और जनसेवा में लगे अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है।पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडेय का यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि कानपुर देहात पुलिस के लिए भी गौरव का विषय माना जा रहा है।

गणतंत्र पर्व पर शेरपुर गुढ़ा में रहा राष्ट्रभक्ति का उल्लास

» वीर सेन यादव ने ध्वजारोहण कर वितरित किए कंबल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात माती। गणतंत्र दिवस पर जनता औद्योगिक इंटर कॉलेज शेरपुर गुढ़ा में गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक एवं समाजवादी पार्टी के प्रांतीय नेता वीर सेन यादव द्वारा ध्वजारोहण कर की गई।समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एचबीटीयू कानपुर के कुलपति प्रोफेसर शमशेर सिंह तथा कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सज्जन लाल वर्मा उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार सिंह एवं प्रबंध समिति अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद यादव ने मुख्य अतिथियों को शाल ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्ति के गीतों एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को देशप्रेम से ओतप्रोत कर दिया। समारोह में वीर सेन यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं सीमा पर शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में लोकतंत्र सेनानी सोने लाल यादव, सपा के कानपुर ग्रामीण पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिव सिंह पाल, सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव शेखू खान, सपा कानपुर देहात के युवा प्रभारी पंडित धर्मेंद्र त्रिवेदी, महेंद्र सिंह बड़े ठाकुर, समाजसेवी राजेश पांडे, प्रधान सुरेंद्र सिंह यादव, प्रधान निर्भय सिंह यादव, प्रधान गुड्डू यादव, सोनी यादव, विजय भान यादव, राजीव द्विवेदी, विजय अग्निहोत्री, डॉ. रोशन लाल, जयदीप सिंह, लाखन सिंह यादव, मोनू यादव, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सुजीत सिंह पाल, छोटे खान, दरोगा जी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रबंधक वीर सेन यादव ने सैकड़ों गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए।

प्रभात फेरी निकाल कर दिया शैक्षिक योजनाओं पर संदेश

पीएम श्री संविलियन विद्यालय तिश्ती में मनाया गया गणतंत्र दिवस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गणतंत्र दिवस पर विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत पीएम श्री संविलियन विद्यालय तिश्ती में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मिशन शक्ति नोडल अर्चना मिश्रा

के निर्देशन में तथा एआरपी पारुल निरंजन एवं विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका दुर्गेश नंदिनी के मार्गदर्शन में हुआ।ध्वजारोहण के बाद उपस्थित बच्चों, शिक्षकों, अतिथियों एवं अभिभावकों ने राष्ट्रगान गाया। इससे पूर्व विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान सूरज, पुनीत, शंकर, शिवा, दीपक, अवनी, दिव्यांशी, राधा, प्रियांशी एवं प्रगति ने नाटक के जरिए विभिन्न शैक्षिक योजनाओं पर प्रभावी संदेश दिया। प्रभात फेरी तिश्ती बाजार से प्रारंभ होकर सहबाजपुर नहरिया चौराहा, हरलाल निवादा तिराहा होते हुए पुनः तिश्ती में आकर संपन्न हुई।अर्चना मिश्रा, हिमांशु गुप्ता, प्रदीप कुमार, वंदना बाजपेई, राहुल कटियार, मुक्ति दीक्षित, वंदना दोहरे, मधु देवी, सुप्रिया, मनीष, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका, रसोइया, ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य तथा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।

200 मीटर दौड़ में छात्राओं ने दिखाया दमखम

» स्नेहलता डिग्री कॉलेज में शुरू हुआ पाँच दिवसीय उमंग महोत्सव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। स्नेहलता गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज, रसूलाबाद में मंगलवार को पांच दिवसीय उमंग महोत्सव का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन कॉलेज के प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता सराग ने फीता काटकर किया। इसके पश्चात उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

इस अवसर पर प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता ने कहा कि उमंग महोत्सव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ छात्रों में नई ऊर्जा, अनुशासन और बौद्धिक क्षमता का विकास करती हैं। उमंग महोत्सव के पहले दिन विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

क्रीडाध्यक्ष जितेंद्र कुमार त्रिपाठी (जीतू) के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं ने 200 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़ में भाग लिया। छात्राओं ने खो-खो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, वहीं छात्रों ने लंबी कूद में अपनी प्रतिभा दिखाई। 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता बेहद रोमांचक रही, जिसे देखने के लिए दर्शकों में खास उत्साह देखा गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. अमित कुमार गुप्ता, राजीव कुमार शुक्ला (राजू), प्रबंधक प्रवेश यादव (छुन्नू), डॉ. संतोष बाजपेई, विमल यादव, सिद्धराम राजपूत, राजीव राजपूत, रामनिहोर शुक्ला, सी.के. त्रिपाठी, अजीत गुप्ता, अनुराधा दुबे, आलोक राजपूत, विवेक पांडेय, दिनेश राजपूत सहित कॉलेज के अन्य शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे।

यूजीसी बिल के विरोध में केशव मधुवन सेवा समिति की बैठक, कानून वापस लेने की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। यूजीसी एक्ट के विरोध में केशव मधुवन सेवा समिति, केशव नगर की एक आवश्यक बैठक केशव मधुवन वाटिका में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महासचिव राजेन्द्र अवस्थी ने की। बैठक में विश्वविद्यालयों में सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने, सवर्ण छात्रों के उत्पीड़न और कथित रूप से भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर गहरी चिंता जताई गई तथा यूजीसी कानून को अविलंब वापस लेने की

मांग की गई।

वक्ताओं ने कहा कि यह कानून हिन्दू समाज को विभाजित करने वाला है और विश्वविद्यालयों में एक वर्ग विशेष को लक्ष्य बनाकर मानसिक प्रताड़ना की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। चेतावनी दी गई कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो निकट भविष्य में देश को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं,

जिसकी शुरुआत विभिन्न छात्र, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के विरोध से हो चुकी है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इसका उदाहरण बताया गया।

राजेन्द्र अवस्थी ने कहा कि हैदराबाद के रोहित बैमुन्ना प्रकरण के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी को प्रत्येक विश्वविद्यालय में समता समिति गठित करने को कहा गया था, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। आरोप लगाया गया कि बाद में ओबीसी को भी पीड़ित श्रेणी में जोड़ दिए जाने से विश्वविद्यालय आरक्षित और अनारक्षित दो वर्गों में बंट गए हैं।

बैठक में कहा गया कि संशोधित एक्ट के तहत समता समिति में सवर्ण प्रतिनिधित्व न होने से निर्णय एकतरफा और विभाजनकारी होंगे, जिससे संविधान में प्रदत्त समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

सैनिक प्रकोष्ठ से जुड़े फ्लाइंग ऑफिसर राधा कृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि यह कानून सभी छात्रों पर समान रूप से लागू न होकर सवर्ण छात्रों को पहले से ही संदिग्ध बना देता है, जिससे उनमें भय और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आशंका जताई कि शिक्षकों और छात्रों को दुर्भावना से झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है।

प्रचार प्रसार मंत्री पी के त्रिपाठी ने कहा कि यूजीसी के नए नियम भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी हैं तथा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को रोकने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इक्विटी नियमों के सेक्शन 3(सी) को चुनौती देने की बात कही।

बैठक में श्याम बिहारी शर्मा, सुरेंद्र सिंह, राम प्रकाश पाण्डेय, बी के तिवारी, राजू निगम, धनराज चंदेल, राजेश त्रिवेदी, शंकरलाल परशुरामपुरिया, सुदीप गर्ग, विनोद कुमार सिंह, ओम प्रकाश गौतम, विकास गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

रिटायर्ड इंजीनियर संघ ने मनाया गणतंत्र दिवस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उप्र विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा (सेनि) संघ की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संघ भवन नेहरू इन्कलेव गोमती नगर में गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई।इस अवसर पर संघ की कार्यकारिणी के प्रान्तीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा, प्रान्तीय महासचिव एस आर सिंह, उपाध्यक्ष एस एन सिंह सहित कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और संघ के सदस्य उपस्थित रहे।

सभी ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम के दौरान सी के चतुर्वेदी सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कर्मचारियों से कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया

।कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिससे पूरे वातावरण में देशभक्ति का भाव व्याप्त रहा।

राम मंदिर परिसर में खुलेंगे कुछ उप मंदिर, बड़ी संख्या में होगी पुजारियों की भर्ती

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। राम जन्मभूमि परिसर में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राम मंदिर में जल्द ही करीब 50 नए पुजारियों की भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया परिसर में स्थित उप-मंदिरों में दर्शन व्यवस्था शुरू होने से पहले पूरी किए जाने की संभावना है, ताकि पूजा-अर्चना और दर्शन सुचारु रूप से संचालित किए जा सकें।श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और पूजा व्यवस्थाओं के विस्तार को देखते हुए अतिरिक्त पुजारियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी क्रम में भर्ती की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि चयनित पुजारी वैदिक परंपराओं में पारंगत होंगे और उन्हें राम मंदिर की धार्मिक मर्यादाओं व परंपराओं के अनुरूप दायित्व सौंपे जाएंगे। राम मंदिर में अभी 20 पुजारी कार्यरत हैं। इन पुजारियों को रामलला व राम दरबार के अलावा शेषावतार व परकोटे के छह मंदिरों के अतिरिक्त यज्ञमंडप, सप्त मंडपम

व कुबेर टीला पर स्थित कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी है।राम मंदिर व राम दरबार के अतिरिक्त सात उप-मंदिरों में नियमित दर्शन शुरू कराने के लिए तीन शिफ्टों व सुबह-शाम की दोनों पालियों में 42 पुजारियों की जरूरत है जो कि आठ-आठ घंटे व उससे अधिक समय तक ड्यूटी कर सकें। इसके अलावा सप्त मंडपम व कुबेर टीला में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक के लिए आठ अतिरिक्त पुजारी की आवश्यकता है। इस तरह से कम से कम 50 पुजारियों की तत्काल आवश्यकता है।

यूजीसी काले कानून को तत्काल वापस लिए जाने के विरोध में किया प्रदर्शन

» राजपूत करणी सेना सवर्ण समाज के लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को दिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद द्य यूजीसी का काला कानून तत्काल वापस न लिया गया तो बच्चों के भविष्य के साथ ही साथ अभिभावकों पर इसका गहरा असर पड़ेगा,यही नहीं आने वाले समय में बच्चों का भविष्य अंधकार मय हो जाएगा द्य इस यूजीसी के काले कानून को तत्काल वापस लिए जाने के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना सवर्ण समाज के लोगों ने एकजुट होकर मंगलवार को ब्रह्म दत्त द्विवेदी स्टेडियम में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए स्टेडियम से बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया है जिसमें कहा है कि यूजीसी का यह काला कानून सवर्णों को कुचलने ,संविधान का अपमान करने और राष्ट्र विभाजन की साजिश रचने वाला है । सेना के जिला अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान ने कहा कि 48 घंटे के अंदर इस क़ानून वापस ना लिया जाए । यह कानून सवर्ण समाज की हड्डियां तोड़ने का हथियार है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसय जैसे राष्ट्र निर्माताओ को गुलामी की बेडिया पहनाने का अपराध है द्य उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज

श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष ने कहा कि UGC के नाम पर बच्चों के भविष्य पर प्रहार किया जा रहा है, और जब भविष्य पर वार हो तो हर पिता, हर माता, हर छात्र योद्धा बनता है। यह लड़ाई किसी दल या जाति की नहीं, यह शिक्षा, सम्मान और आने वाली पीढ़ी की रक्षा की लड़ाई है। जो अपने बच्चों को डर में नहीं, सम्मान में जीते देखना चाहता है। नारेबाजी करते हुए कहाकि वह आज घर में नहीं बैठेगा। शब्द हमारे शस्त्र हैं, एकता हमारी ढाल है, संविधान हमारा रणघोष यूजीसी कानून वापस लो ! शिक्षा बचाओ देश बचाओ !

ने सदियों से भारत को ज्ञान, शौर्य और समृद्धि दी है अब यह ज़हरीला कानून हमे सड़क पर ला रहा है द्य बाबा साहब अंबेडकर का सपना समानता का था ना कि सवर्ण हत्या का यह कानून सामाजिक आग लगने वाला कुचक्र है हम सहन नहीं करेंगे हमारी मांग स्पष्ट है काला कानून तुरंत रद्द हो उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर सवर्ण समाज का लाखों में होने वाला आंदोलन संपूर्ण भारत में शुरू होगा उसे रोकने के लिए तत्काल इस कानून को वापस दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा जिला अध्यक्ष अमन दुबे, रविंद्र सिंह अभिषेक दुबे अनु दुबे संतोष दिक्षित राघवेंद्र मिश्र अनंत चतुर्वेदी अश्विनी मिश्र सहित सैकड़ो लोग मौजूद रहे।

फर्जी कागज़, झूठे शपथपत्र और सरकारी संरक्षण?

पेंशन पर 'पुनर्विवाह का पर्दा'

» दूसरी शादी, सरकारी नौकरी, फिर भी बेटी के नाम पारिवारिक पेंशन!

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। उत्तर प्रदेश में ईमानदार शासन और ÷जीरो टॉलरेंस÷ की नीति के बीच राजस्व गबन और पेंशन फ्रॉड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।

आरोप है कि लघु सिंचाई विभाग, अयोध्या में कार्यरत प्रिया कनौजिया ने तथ्यों को छुपाकर, फर्जी दस्तावेजों और भ्रामक शपथपत्रों के सहारे अपने मृतक प्रथम पति की पारिवारिक पेंशन वर्षों तक हासिल की वह भी तब, जब उन्होंने दूसरी शादी एक सरकारी कर्मचारी से कर ली और स्वयं भी सरकारी सेवा में हैं।

बता दें कि 10 दिसंबर 2017 को प्रिया कनौजिया ने अपने ही विभाग के मृतक आश्रित कर्मचारी देवेन्द्र (कनिष्ठ सहायक) से पुनर्विवाह कर लिया।

इसके बावजूद, पूर्व पति स्व. उमेश कनौजिया (बोरिंग टेक्नीशियन) की पारिवारिक पेंशन अपनी बेटी इशिता के नाम पर ली जाती रही। चौंकाने वाली बात यह कि 06 फरवरी 2017 को प्रिया कनौजिया और सास-ससुर के बीच लिखित सुलहनामा हुआ था, जिसमें साफ था दूसरी शादी के बाद न तो वह और न ही बेटी किसी भी प्रकार का लाभ लेंगी।

यही सुलहनामा बाद में छुपा लिया गया। आरोप है कि वाद संख्या 19/2018 (पारिवारिक न्यायालय, फैजाबाद) में झूठे शपथपत्र, परिवार के वास्तविक हकदारों (दादा-दादी, चाचा) को जानबूझकर न बुलाना, और महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर दिनांक 05 जनवरी 2022 को नैसर्गिक माता संरक्षक का आदेश हासिल कर लिया गया। जबकि उसी केस में द्वितीय पति देवेन्द्र (सरकारी सेवक) ने कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने इशिता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है और उसका पूरा भरण-पोषण वे और उनकी पत्नी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी को शिकायत भेजी

सरकारी नियम साफ कहते हैं यदि पुनर्विवाह के बाद माता और नया पति दोनों सरकारी सेवा में हों और भरण-पोषण में सक्षम हों, तो पारिवारिक पेंशन का आधार समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, संयुक्त निदेशक पेंशन, अयोध्या मंडल ने भी 08 अप्रैल 2022 को पत्र जारी कर साफ कहा था कुमारी इशिता पारिवारिक पेंशन की पात्र नहीं है। इसके बावजूद, 07 जून 2022 को तथ्यों को फिर से छुपाकर पत्र दिया गया और 05 जुलाई 2022 को पेंशन व एरियर जारी करा लिया गया। अधिवक्ता एम.पी. सिंह द्वारा यह पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत के रूप में भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है आरोपी सरकारी कर्मचारी का निलंबन, बेटी के नाम चल रही पारिवारिक पेंशन तत्काल बंद, पेंशन व एरियर की पूरी वसूली फर्जीवाड़ा, राजस्व गबन और कदाचार में वैधानिक कार्रवाई की जाए।

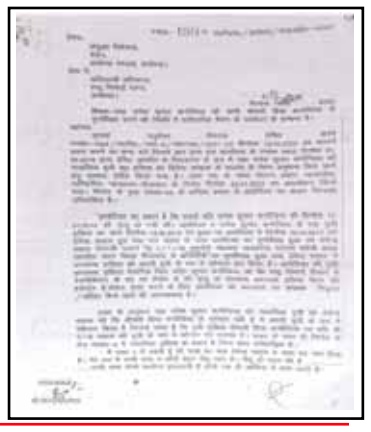

शंकराचार्य विवाद के बीच जीएसटी डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा

डिप्टी कमिश्नर ने कहा सीएम योगी का अपमान बर्दास्त नही

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।रामनगरी अयोध्या, जहां मर्यादा और मर्यादाओं की कसौटी सदियों से तय होती रही है, वहां से इस बार कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना नहीं—बल्कि एक इस्तीफा उठा है। ऐसा इस्तीफा, जो कागज़ पर कम और अंतरात्मा पर ज़्यादा लिखा गया है। शंकराचार्य विवाद के बीच जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को दो पन्नों का इस्तीफा भेजकर न सिर्फ़ अपने पद से हटने का निर्णय लिया, बल्कि व्यवस्था के भीतर बैठे व्यक्ति की वह पीड़ा उजागर कर दी, जो अक्सर फाइलों के नीचे दबा दी जाती है।प्रशांत कुमार सिंह का कहना है जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, जिस प्रदेश से मुझे वेतन मिलता है, मैं उसी का पक्षधर हूं। यह कोई प्रशासनिक बयान नहीं था, यह आत्मसम्मान का उद्घोष था। पिछले तीन दिनों से भीतर ही भीतर टूटते रहे एक अधिकारी ने अंततः वह कर दिखाया, जो आमतौर पर कुर्सी से चिपकी व्यवस्था में असंभव माना जाता है। शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी ने उन्हें गहरे तक आहत किया। उनके शब्दों में सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, सवाल लोकतंत्र के सम्मान का था।

यूजीसी पर न बंटने पाए हिन्दू समाज: तोगड़िया

» अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीणभाई तोगड़िया अयोध्या पहुंचे

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। हिंदू राष्ट्रवादी नेता, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता एवं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीणभाई तोगड़िया अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्रीरामलला का दर्शन-पूजन किया, जिसके उपरांत अयोध्या में अपने जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की।

मीडिया से बातचीत में प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि उन्हें श्रीरामलला के दर्शन-पूजन का अवसर मिला। शंकराचार्य बनाम प्रशासन के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक ओर पूज्य शंकराचार्य हैं और दूसरी ओर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी हैं। धर्म की रक्षा करना दोनों का कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को सलाह देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनका विश्वास है कि दोनों आपसी संवाद से रास्ता निकालकर मामले का समाधान करेंगे और हिंदुओं को एकजुट रखने का कार्य करेंगे। यूजीसी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली, हिंदू समाज किसी भी कीमत पर बंटना नहीं चाहिए और दूसरी, हिंदू चाहे किसी भी जाति का हो, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कॉलेजों में उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

अयोध्या पहुंची 10 जापानी महिलाओं ने किया रामलला का दर्शन

» जापानी महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ 'जय श्री राम' का उद्घोष किया

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। आध्यात्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा लिए जापान से आईं 10 महिलाओं के एक विशेष समूह ने सोमवार को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन से पहले सोहावल तहसील स्थित प्रसिद्ध मां ज्वाला देवी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब जापानी महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाए।जानकारी के अनुसार, यह सभी महिलाएं सोहावल तहसील क्षेत्र के गालिबपुर गांव निवासी योगाचार्य नीरज सिंह की शिष्याएं हैं।

भारत आगमन के बाद योगाचार्य ने सबसे पहले उन्हें अपनी जन्मभूमि गालिबपुर का भ्रमण कराया और गांव की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं से अवगत कराया। इसके पश्चात योगाचार्य इन जापानी महिलाओं को मां ज्वाला देवी मंदिर लेकर पहुंचे। यहां महिलाओं ने पूरे विधि-विधान के साथ देवी मां की पूजा-अर्चना की। जापानी महिलाओं की श्रद्धा और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान को देखकर स्थानीय श्रद्धालु भी भावविभोर नजर आए। योगाचार्य नीरज सिंह ने बताया कि यह समूह विशेष रूप से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जापान से भारत आया है। उन्होंने कहा कि जापान में भी योग, ध्यान और भारतीय दर्शन के प्रति लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है और भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन से वहां के लोग प्रेरणा ले रहे हैं।

18 साल बाद भारत-यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील

2027 से लागू होने की संभावना, 'मदर ऑफ ऑल डील' करार

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच 18 वर्षों की लंबी और जटिल बातचीत के बाद आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सहमति बन गई है। मंगलवार को आयोजित 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने इस ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा की। न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस डील को वर्ष 2027 से लागू किए जाने की संभावना है।

यह समझौता वैश्विक आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपीय यूनियन दूसरे स्थान पर है। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25 प्रतिशत और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं।

लग्जरी कारें और शराब होंगी सस्ती

एफटीए के लागू होते ही भारतीय बाजार में यूरोप से आने वाली लग्जरी वस्तुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी यूरोपीय लग्जरी कारों पर आयात शुल्क 110त्न से घटकर करीब 10त्न किए जाने का प्रस्ताव। यूरोपीय शराब और वाइन पर मौजूदा 150% टैरिफ घटकर 20-30% तक आ सकता है। विदेशी शराब की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की संभावना है। व्यापार के साथ रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के साथ भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच रणनीतिक सहयोग को भी नई मजबूती मिली है। भारत-ईयू सुरक्षा और रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर में ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास और विदेश मंत्री एस. जयशंकर रहे मौजूद रहे। काजा कलास ने कहा कि समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर विशेष जोर रहेगा। जब दो बड़े लोकतांत्रिक देश साथ काम करते हैं, तो एक मजबूत सुरक्षा और रक्षा ढांचा तैयार होता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए इसे अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी समझौता बताया। उन्होंने कहा कि यह डील दोनों पक्षों में निवेश बढ़ाएगी और लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड डीलः प्रमुख बिंदु

- **18 साल बाद ऐतिहासिक सफलताः** भारत-ईयू एफटीए पर 2007 से चल रही बातचीत आखिरकार निर्णायक मुकाम पर पहुंची
- **2027 से लागू होने की संभावनाः** कानूनी और संसदीय प्रक्रियाओं के बाद डील को अमल में लाया जाएगा
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असरः** भारत और ईयू मिलकर विश्व जीडीपी का करीब 25% और वैश्विक व्यापार का लगभग 33% नियंत्रित करते हैं
- **लग्जरी कारें होंगी सस्तीः** बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क 110% से घटकर 10% तक आने का प्रस्ताव
- **विदेशी शराब पर टैक्स कटौतीः** यूरोपीय शराब और वाइन पर टैरिफ 150% से घटकर 20-30% किए जाने की तैयारी
- **निवेश और रोजगार को बढ़ावाः** डील से मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, फार्मा और आईटी सेक्टर में बड़े निवेश की उम्मीद
- **भारतीय निर्यातकों को फायदाः** टेक्सटाइल, चमड़ा, ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज और कृषि उत्पादों के लिए ईयू बाजार और खुला
- **रणनीतिक साझेदारी मजबूतः** व्यापार के साथ भारत-ईयू सुरक्षा और रक्षा सहयोग को नई मजबूती
- **चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिशः** ईयू के लिए भारत एक भरोसेमंद वैकल्पिक सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में उभरा
- **'मदर ऑफ ऑल डील':** यूरोपीय नेतृत्व ने इसे अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक ट्रेड समझौता बताया

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ले ली है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मंगलवार सुबह राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। बेमौसम बरसात और तेज सर्द हवाओं ने ठंडक को और बढ़ा दिया, जिससे सुबह के समय लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई।मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, मंगलवार को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश हुई है। इसके साथ ही कई स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने से ठंड का असर और तेज हो गया है।

बारिश, ठंडी हवाओं और कोहरे के संयुक्त प्रभाव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं ठंड बढ़ने के कारण लोग घरों से निकलने में हिचकिचाते नजर आए। ग्रामीण इलाकों में भी सर्द मौसम का असर देखा गया, जहां अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया जा रहा है।

- **सुबह-सुबह बारिश और सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, जनजीवन हुआ प्रभावित**
- **बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग में भी बरसात की संभावना**

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है, जिससे ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम हैं।

चित्रकूट : मासूम आयुष की हत्या से खुखी व्यापारियों ने दी श्रद्धांजलि

स्वराज इंडिया न्यूज

चित्रकूट। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन शानू गुप्ता के कार्यालय शंकर बाज़ार, कर्वी में चित्रकूट के बेटे आयुष की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आयुष को नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित की।

बताया गया कि बरगढ़, चित्रकूट निवासी कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के पुत्र आयुष की मो. कल्लू और इरफान द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य घटना से व्यापारिक समाज में भारी आक्रोश है। कर्वी के व्यापारियों ने इसे अत्यंत हृदयविदारक बताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन शानू गुप्ता ने कहा कि व्यापारी पुत्र आयुष की सुनियोजित और बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने मांग की कि एक आरोपी को जहां सजा मिल चुकी है, वहीं दूसरे आरोपी इरफान को भी मृत्यु दंड दिया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परिवार को सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। मंडल मंत्री विनोद आर्य, महामंत्री शेशू जायसवाल, जिलाध्यक्ष प्रमोद जायसवाल, महिला अध्यक्ष शकुंतला गुप्ता, युवा अध्यक्ष किशन सोनी, विष्णु केसरवानी, सुनील जायसवाल, सीताराम श्रीवास्तव, नारायण दास केसरवानी, ललित जायसवाल, राविराज अग्रहरि, संतोष डिक्सी, करामत अली, विवेक पाठक, रूपेश निगम, संध्या गुप्ता, अमित काजू गुप्ता, संजय सोनी, मनीष गुप्ता, दशरथ केसरवानी, सुनील सोनी, संतोष गुप्ता, कमलेश साहू, संजीव गुप्ता, स्वतंत्र गुप्ता, अतुल अग्रहरि, तन्नू अग्रहरि, पप्पू साहू, राजेंद्र सोनी, आयुष सिंह, रवि अग्रहरि, नारायणदास गुप्ता, विनोद कुमार, रामप्रकाश केसरवानी, अनिल कुमार सिंह, राजाराम विश्वकर्मा, डॉ. साब, शिवम कुमार सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। व्यापारियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक आयुष को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com